

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1,

देहरादून: दिनांक ०६ अप्रैल, 2015

विषय:-

श्री केदारपुरी में अवस्थित भवन, लॉज स्वामियों/तीर्थ पुरोहितों के पुनर्वास एवं सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया वर्ष 2013 में जून माह में घटित प्राकृतिक आपदा से पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त श्री केदारपुरी मन्दिर क्षेत्र में अवस्थित भवन, लॉज स्वामियों/तीर्थ पुरोहितों के भवन आदि को पुनर्वासित किये जाने तथा श्री केदारपुरी में प्राकृतिक आपदा के पश्चात जीर्ण-शीर्ण अवस्था में खड़े निजी भवनों के ध्वस्तीकरण तथा उनको पुनर्वासित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है:-

- 1) श्री केदारपुरी मंदिर क्षेत्र में अवस्थित भवनों, लाजों तथा अन्य व्यवसायियों/तीर्थ पुरोहितों आदि का विवरण समुचित जांच व सम्मस्त अभिलेखों के अनुरूप जिलाधिकारी द्वारा दिया जायेगा।
- 2) ध्वस्त किये जाने वाले भवनों का वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार वास्तविक निर्मित क्षेत्रफल (स्वामित्व + कब्जे की भूमि पर हुआ निर्माण) पर मुआवजा दिया जायेगा।
- 3) उक्त formula के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने हेतु पूर्णतः क्षतिग्रस्त/wash out हुए भवनों के स्वामी भी पात्र होंगे।
- 4) श्री केदारपुरी क्षेत्र में स्थित व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन हेतु वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार रू० 26,990/- सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर का निर्धारण किया गया है। (सुपर एरिया के आधार पर उक्त निर्दिष्ट दरों में अकृषक भूमि के वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार रू० 890/- प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि की कीमत भी सम्मिलित है)।
- 5) भवन ध्वस्तीकरण की कार्यवाही चरणबद्ध रूप से सहमति के आधार पर की जायेगी।
- 6) अवस्थित भवनों के ध्वस्तीकरण से पूर्व प्रशासन द्वारा भवन स्वामी की उपस्थिति में निर्मित क्षेत्रफल व अध्यासन की भूमि का (नाप जोख हेतु) सर्वेक्षण कराया जायेगा। इस कार्य हेतु संयुक्त टीम गठित की जायेगी, जिसमें राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा क्षेत्र में कार्यरत संस्था NIM के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से सम्मिलित किये जायेंगे।
- 7) भवन ध्वस्तीकरण से पूर्व उसमें रखी हुई उपयोगी सामग्री की फर्द तैयार कर भवन के ध्वस्तीकरण से पूर्व सुरक्षित भण्डारित किया जायेगा।
- 8) ध्वस्तीकरण प्रक्रिया की सम्पूर्ण फोटोग्राफी/विडियोग्राफी भवन स्वामी अथवा उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में करायी जायेगी।
- 9) श्री केदारपुरी में भवनों के ध्वस्तीकरण उपरान्त भूखण्ड का उपचार व समतलीकरण का मास्टर प्लान के अनुसार अन्त में भवनों के निर्माण योग्य कुल उपलब्ध भूमि को प्रभावित को pro rata basis पर आवंटित किया जायेगा।

- 10) प्रभावित व्यक्ति को श्री केदारनाथ के भू-अभिलेखों के अनुसार उसकी विधिक स्वामित्व की भूमि के कुल रकबे के अनुपात में उसकी वर्तमान भूमि के स्थान/निकट के स्थान पर भूमिधरी अधिकार दिया जायेगा।
- 11) प्रभावित व्यक्ति के वर्तमान स्वामित्व के भवन के विधिक निर्मित क्षेत्रफल के अनुरूप प्रभावित व्यक्ति को आवंटित की गई भूमि पर यथासम्भव मिलानी क्षेत्रफल का नवनिर्माण सरकार द्वारा करके दिया जायेगा।
- 12) श्री केदारनाथ धाम में सरकार द्वारा निर्मित कर दिये जाने वाले भवनों को केदारनाथ विनियमित क्षेत्र द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाया जायेगा तथा भवन के डिजाइन व निर्माण के प्रकार के सम्बन्ध में लाभार्थी को विकल्प प्रदान कर उसकी सहमति से ही अन्तिम विनिश्चय किया जायेगा।
- 13) यदि भवन स्वामी का वर्तमान विधिक निर्मित क्षेत्रफल/विधिक स्वामित्व की भूमि एवं भविष्य में मिलने वाली भूमिधरी भूमि व नव निर्माण के क्षेत्रफल में अन्तर हो तो,
(क) लाभार्थी को केदारपुरी के बाहर जनपद में अन्य सुरक्षित स्थान पर शेष भूमि आवंटित कर शेष निर्माण करके दिया जायेगा।
(ख) लाभार्थी उपरोक्त हेतु अनिच्छुक होने की दशा में शेष भूमि एवं शेष निर्माण के क्षेत्रफल का उपरोक्तानुसार निर्धारित दरों के अनुरूप मुआवजा देय होगा।
- 14) पुनर्वास प्रक्रिया से आच्छादित व्यवसायियों/लाभार्थियों की सूची व क्षेत्रफल आदि का विवरण अंतिम करने के उपरान्त इस समस्त विवरण को डिजिटल स्वरूप में भी रखा जायेगा। अंतिम विवरण तैयार हो जाने के उपरान्त मुआवजा वितरण की कार्यवाही की जायेगी। इस समस्त कार्यवाही को शासकीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
- 15) ऐसे प्रभावित व्यक्ति जिनके भवन/व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः राज्य सरकार की स्वामित्व की भूमि पर निर्मित थे, उन्हें द्वितीय प्राथमिकता के आधार पर यथासम्भव उक्त पुनर्वास प्रक्रिया से आच्छादित किया जायेगा।
- 16) श्री केदारनाथ मन्दिर से नीचे की ओर वैलीब्रिज तक 50 फीट चौड़ा पैदल रास्ता बनाया जायेगा, साथ ही श्री केदारनाथ मन्दिर प्लेटफार्म के दांयी एवं बांयी ओर भी 30-30 फीट जगह खाली छोड़ी जायेगी, उक्त की परिधि में आने वाले भवन/भूमि स्वामियों को special package प्रदान किया जायेगा।
- 17) उपरोक्त बिन्दु 14 से आच्छादित होने वाले प्रभावितों को उनके वर्तमान कब्जे की कुल भूमि के समतुल्य क्षेत्रफल की केदारपुरी में अवस्थित Prime Government land (NZA) पहले आओं, पहले पाओं के सिद्धान्त पर आवंटित की जायेगी तथा उनके कुल निर्मित क्षेत्रफल के समतुल्य नवीन निर्माण सरकार द्वारा करके दिया जायेगा। मुआवजा सम्बन्धी अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।
- 18) भवन ध्वस्तीकरण से पूर्व प्रभावित व्यक्ति एवं पुनर्वास/विस्थापन आयुक्त के मध्य शपथ पत्र पर उपरोक्त शर्तों पर सहमति अभिलिखित की जायेगी।

- 19) दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त उक्त व्यावसायिक भवनों हेतु प्रशासन द्वारा सम्बन्धितों को पूर्व निर्गत राहत सहायता की धनराशि को उक्तानुसार अनुमन्य कुल मुआवजा की धनराशि में समायोजित किया जायेगा।
- 20) प्रभावितों द्वारा उपरोक्त पुनर्वास प्रक्रिया पर असहमति (resistance) होने की दशा में सम्बन्धितों के साथ final settlement करने हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग/पुनर्वास एवं विस्थापन आयुक्त, केदारनाथ को उनके साथ negotiation कर निर्धारित मुआवजा दर से अधिक प्रदान कर सहमति प्राप्त करने हेतु अधिकृत होंगे तथा ऐसे प्रकरण के सम्बन्ध में कारण अभिलिखित करते हुए व सम्यक् अभिलेखों सहित जिलाधिकारी/पुनर्वास एवं विस्थापन आयुक्त द्वारा शासन से स्वीकृति/कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रभारी सचिव

संख्या-919-()/XVIII-(2)/2015-15(17)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का सतत् पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।
- ✓ 5- निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- अधिशासी निदेशक, डी०एम०एम०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रभारी सचिव

